भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2101
सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

राष्ट्रीय शहरी युवक रोजगार कार्यक्रम

2101. श्री दीपक अधिकारी (देव):
डॉ. शशि थरूर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी रिकार्ड के अनुसार देश में विगत दस वर्षों के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कोई राष्ट्रीय शहरी युवक रोजगार कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने नए रोजगारों को पंजीकृत किया गया है;

(ङ) क्या रोजगार के अवसरों के सृजन में योगदान करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (च): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (%में)	यूआर (% में)
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आकड़ें दर्शाते हैं कि डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है और बेरोजगारी दर में पिछले कुछ वर्षों में कमी की प्रवृत्ति है।

देश में अनुमानित बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार अनुमान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17 करोड़ है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय का राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल (www.ncs.gov.in) पोर्टल के माध्यम से नौकरी खोज और मिलान, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, इंटर्नशिप आदि जैसी विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। दिनांक 30 जुलाई 2024 तक, एनसीएस प्लेटफॉर्म में 30.92 लाख से अधिक नियोक्ता और 20 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, एनसीएस पोर्टल पर 1.09 करोड़ रिक्तियां पोस्ट की गईं और 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से पोर्टल पर जुटाई गई रिक्तियों की कुल संख्या 2.9 करोड़ से अधिक है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौर, **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा की है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 05.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2101 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य-वार विवरण 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	बेरोजगारी दर (% में)					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आंध्र प्रदेश	4.5	5.3	4.7	4.1	4.2	4.1
अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7	6.7	5.7	7.7	4.8
असम	7.9	6.7	7.9	4.1	3.9	1.7
बिहार	7.0	9.8	5.1	4.6	5.9	3.9
छत्तीसगढ	3.3	2.4	3.3	2.5	2.4	2.4
दिल्ली	9.4	10.4	8.6	6.3	5.3	1.9
गोवा	13.9	8.7	8.1	10.5	12.0	9.7
गुजरात	4.8	3.2	2.0	2.2	2.0	1.7
हरियाणा	8.4	9.3	6.4	6.3	9.0	6.1
हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1	3.7	3.3	4.0	4.3
झारखंड	7.5	5.2	4.2	3.1	2.0	1.7
कर्नाटक	4.8	3.6	4.2	2.7	3.2	2.4
केरल	11.4	9.0	10.0	10.1	9.6	7.0
मध्य प्रदेश	4.3	3.5	3.0	1.9	2.1	1.6
महाराष्ट्र	4.8	5.0	3.2	3.7	3.5	3.1
मणिपुर	11.5	9.4	9.5	5.6	9.0	4.7
मेघालय	1.6	2.7	2.7	1.7	2.6	6.0
मिजोरम	10.1	7.0	5.7	3.5	5.4	2.2
नागालैंड	21.4	17.4	25.7	19.2	9.1	4.3
ओडिशा	7.1	7.0	6.2	5.3	6.0	3.9
पंजाब	7.7	7.4	7.3	6.2	6.4	6.1
राजस्थान	5.0	5.7	4.5	4.7	4.7	4.4
सिक्किम	3.5	3.1	2.2	1.1	1.6	2.2
तमिलनाडु	7.5	6.6	5.3	5.2	4.8	4.3
तेलंगाना	7.6	8.3	7.0	4.9	4.2	4.4
त्रिपुरा	6.8	10.0	3.2	3.2	3.0	1.4
उत्तराखंड	7.6	8.9	7.1	6.9	7.8	4.5
उत्तर प्रदेश	6.2	5.7	4.4	4.2	2.9	2.4
पश्चिम बंगाल	4.6	3.8	4.6	3.5	3.4	2.2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8	13.5	12.6	9.1	7.8	9.7
चंडीगढ़	9.0	7.3	6.3	7.1	6.3	4.0
दादरा एवं नगर हवेली	0.4	1.5	3.0	4.2	5.2	2.5
दमन और दीव	3.1	0.0	2.9			
जम्मू और कश्मीर	5.4	5.1	6.7	5.9	5.2	4.4
लद्दाख	-	-	0.1	2.9	3.3	6.1
लक्षद्वीप	21.3	31.6	13.7	13.4	17.2	11.1
पुडुचेरी	10.3	8.3	7.6	6.7	5.8	5.6
अखिल भारत	6.0	5.8	4.8	4.2	4.1	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई